



एन.सी.आर. क्षेत्र में
वायु प्रदूषण के निदान के लिए
ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान
के कार्यान्वयन हेतु
मार्ग-निर्देश



पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

संजीव सरन,

आई.ए.एस.

अपर मुख्य सचिव

वन एवं वन्यजीव, पर्यावरण,
वाह्य सहायतित परियोजनाएं,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

601, बापू भवन, सचिवालय

कार्यालय-2238669, फ़ैक्स-2235206

ई-मेल : psforest2015@gmail.com



संजीव सरन

आई.ए.एस.

प्राक्कथन

जहाँ स्वच्छ पर्यावरण सभी नागरिकों का अधिकार है, वहीं पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखना हम सभी का दायित्व भी है। मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के निदान के लिये भारत सरकार द्वारा ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को दिया गया है। इस एक्शन प्लान का कार्यान्वयन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना है। उक्त एक्शन प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये आवश्यक है कि सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्लान में निहित एक्शन बिन्दुओं तथा अपने दायित्वों की पूर्ण जानकारी हो। अतः फील्ड-लेवल कार्मिकों तक एक्शन प्लान के बिन्दुओं की जानकारी सरल एवं ग्राह्य तरीके से दिये जाने हेतु यह मार्गनिर्देशिका तैयार की गयी है। साथ ही सम्बन्धित विभागों द्वारा एक्शन बिन्दुओं के अनुपालन की रिपोर्ट सुगमता पूर्वक प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यविधि भी इस मार्गनिर्देशिका में उल्लिखित है।

मुझे आशा व पूर्ण विश्वास है कि यह मार्गनिर्देशिका ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान के सफल क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित कार्यदायी विभागों का पथ-प्रदर्शन करने में सहायक होगी जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के नियंत्रण व निदान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

दिनांक: 14-02-2017

(संजीव सरन)



विषय सूची

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान क्या है?	2
3.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान को लागू किये जाने हेतु उत्तरदायी विभाग/संस्थाएं एवं कार्मिक	3
4.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान को लागू किये जाने की कार्यविधि	4
5.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के मुख्य स्मरण योग्य बिन्दु	5
6.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु विकसित वेब-पोर्टल	6
7.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के अन्तर्गत निर्धारित एक्शन बिन्दु – परिशिष्ट-1	7
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-107, दिनांक 12.01.2017 – परिशिष्ट-2	16
9.	वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.01.2017 का कार्यवृत्त– परिशिष्ट-3	43
10.	ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन हेतु EPCA द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.01.2017 का कार्यवृत्त– परिशिष्ट-4	49



प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के दृष्टिगत मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न स्तरों के वायु प्रदूषण के निदान के लिए केन्द्र सरकार की अधिसूचना संख्या-107, दिनांक 12-01-2017 (परिशिष्ट-2) द्वारा ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान अधिसूचित किया गया है। इस प्लान के कार्यान्वयन का दायित्व पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को दिया गया है। ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू किये जाने तथा सम्बन्धित विभागों के फील्ड-लेवल कार्मिकों तक उक्त प्लान के अनुसार कार्यवाही के बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मार्ग-निर्देशिका तैयार की गई है।

ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान क्या है ?

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12-01-2017
के माध्यम से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक
के आधार पर वायु प्रदूषण के
निम्न चार स्तर निर्धारित किये गये हैं :-

Severe + or Emergency	PM _{2.5} 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से अथवा PM ₁₀ 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से अधिक 48 घण्टे तक बने रहने की स्थिति।
Severe	PM _{2.5} 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से अथवा PM ₁₀ 430 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ से अधिक होने की स्थिति।
Very poor	PM _{2.5} 121 से 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य अथवा PM ₁₀ 351 से 430 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य होने की स्थिति।
Moderate to poor	Poor - PM _{2.5} 91 से 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ अथवा PM ₁₀ 251 से 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य होने की स्थिति। Moderate - PM _{2.5} 61 से 90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ अथवा PM ₁₀ 101 से 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य होने की स्थिति।

उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किये गये उपायों को ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान कहा गया है।

ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान को लागू किये जाने हेतु उत्तरदायी विभाग/
संस्थाएं एवं कार्मिक

क्र.सं.	विभाग/संस्था	कार्मिक
1.	परिवहन	आर०टी०ओ०/ए०आर०टी०ओ०/ परिवहन निरीक्षक
2.	कृषि	जिला कृषि अधिकारी, उपनिदेशक, सहायक निदेशक
3.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशोषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता
4.	नगर विकास एवं जल निगम	नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, अधिशोषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सैनेटरी इन्स्पेक्टर
5.	लोक निर्माण विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	अधीक्षण अभियन्ता, अधिशोषी अभियन्ता, परियोजना प्रबन्धक, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता
6.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता
7.	आवास एवं शहरी नियोजन	नगर नियोजक, अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशोषी अभियन्ता
8.	ऊर्जा	महाप्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशोषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता
9.	गृह	पुलिस अधीक्षक (यातायात), पुलिस अधीक्षक (कानून व्यवस्था), उप पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष, निरीक्षक, उपनिरीक्षक
10.	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी
11.	भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग	खनन अधिकारी, पर्यवेक्षक
12.	पर्यावरण	उपनिदेशक, सहायक निदेशक, तकनीकी सहायक

ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान को लागू किये जाने की कार्यविधि

पूर्व-तैयारी

चर्तुस्तरीय प्रशिक्षण

अ. राज्य स्तरीय अधिकारियों का ई०पी०सी०ए० द्वारा।

ब. कार्यान्वयन अधिकारियों का उ०प्र०,

एन० सी० आर० स्तर पर पर्यावरण विभाग द्वारा।

स. जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा।

द. अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों का सम्बन्धित विभागों द्वारा।

भारत सरकार से वायु-प्रदूषण अलर्ट प्राप्त होने पर ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान के अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा संगत कार्यवाहियां तुरन्त लागू की जानी होंगी, जिस हेतु पूर्व से ही तैयारी की आवश्यकता होगी। अतः सम्बन्धित विभागों द्वारा एक्शन बिन्दुओं से सम्बन्धित पूर्व-तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित करनी अनिवार्य होंगी।

निर्धारित एक्शन बिन्दुओं पर कार्यवाही

ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान में निर्धारित प्रदूषण स्तरों के अनुसार विभिन्न विभागों से वांछित कार्यवाही हेतु बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जिन पर कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

विभिन्न प्रदूषण स्तरों के अनुसार ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान को लागू किये जाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली पूर्व-तैयारियों व निर्धारित एक्शन-बिन्दुओं का विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।



ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के मुख्य स्मरण योग्य बिन्दु

1. ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2016 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
2. ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ई० पी० सी० ए०) को दिया गया है।
- 3- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार वायु प्रदूषण के चार स्तर निर्धारित किये गये हैं:
 - Severe + or emergency
 - Severe
 - Very poor
 - Moderate to poor
- 4- भारत सरकार से वायु प्रदूषण अलर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित विभागों को अवगत कराया जायेगा, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण स्तर के अनुसार ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान में निर्धारित कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जायेगी।
- 5- सम्बन्धित विभागों द्वारा ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के कार्यवाही बिन्दुओं का अनुपालन वेब पोर्टल www.upecp.in पर भरते हुए अनुपालन रिपोर्ट की हस्ताक्षरित हार्ड-कॉपी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

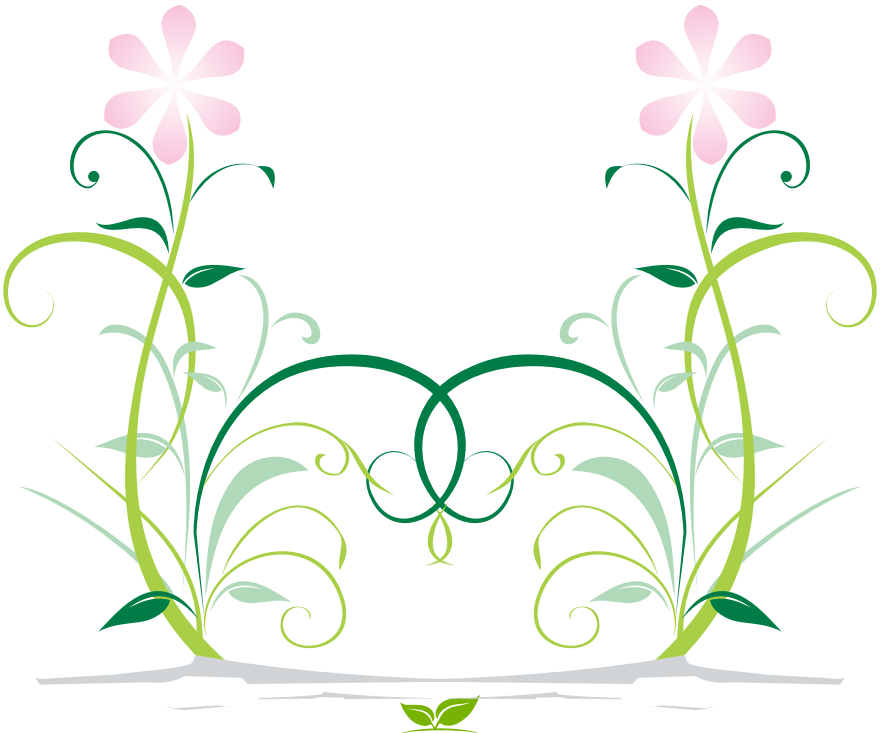
ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु विकसित वेब-पोर्टल

- 1- ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान के अनुपालन की रिपोर्ट सम्बन्धित विभागों द्वारा सुगमतापूर्वक प्रस्तुत किये जाने हेतु एक वेब-पोर्टल www.upecp.in तैयार किया गया है।
- 2- सम्बन्धित विभागों को वेब-पोर्टल पर अनुपालन प्रस्तुत करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करना होगा।
- 3- सम्बन्धित विभागों को उक्त वेब-पोर्टल के एक्शन बिन्दुओं का अनुपालन अंकित करने हेतु यूजर आईडी व पासवर्ड दिये जायेंगे।
- 4- वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार वेब-पोर्टल पर परिशिष्ट-1 में दिया गया एक्शन बिन्दुओं का टेम्पलेट दिखने लगेगा, जिसमें दर्शाये गये एक्शन बिन्दुओं के समक्ष सम्बन्धित नोडल अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित अनुपालन की आख्या वेब-पोर्टल पर अंकित की जायेगी।
- 5- प्राप्त अनुपालन आख्या के संतोषजनक न होने की स्थिति में पर्यावरण विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग को वेब-पोर्टल पर अलर्ट भेजते हुए पुनरीक्षित आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये जायेंगे।
- 6- वेब-पोर्टल पर अनुपालन सूचना अंकित किये जाने की सुविधा से सम्बन्धित विभागों का समय बचेगा तथा अनुपालन सूचना त्वरित गति से संकलित हो सकेगी, जो कि ई-गवर्नेंस हेतु प्रभावी कदम सिद्ध होगा।



परिशिष्ट-1

ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लान
के अन्तर्गत
निर्धारित एक्शन बिन्दु



1. Severe + or Emergency (PM_{2.5} 300 µg/m³ से अथवा PM₁₀ 500 µg/m³ से अधिक 48 घण्टे तक बने रहने की स्थिति)
 अ) पूर्व तैयारी के एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	दिल्ली सीमा से पूर्व भारवाहक वाहनों को प्रत्यावर्तित किया जाना	वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण अवरोध मुक्त प्रत्यावर्तन स्थलों का चिन्हीकरण डिस्पले साइनेज (लूट एवं दूसरी) की स्थापना प्रचार प्रसार—अग्रिम चेतावनी वैकल्पिक मार्गों का सुदृढीकरण	ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग	आर0टी0ओ0, पुलिस अधीक्षक (यातायात), अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0	
2.	बिल्डरों आदि को निर्माण कार्य बन्द करने हेतु नोटिस एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से चेतावनी दिया जाना	निर्माण साइटों का चिन्हीकरण	आवास एवं नगर नियोजन, औद्योगिक विकास, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0	
3.	निर्माण स्थलों के निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर निरीक्षण दलों का गठन	कर्मियों को चिन्हित करते हुए दलों का गठन किया जाना प्रशिक्षण	आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, नगर विकास, लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0, नगर आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट	
4.	ऑड/ ईवन सिस्टम लागू करने की तैयारी	प्रचार प्रसार प्रतिबन्ध से मुक्त वाहनों के सम्बन्ध में निर्णय अर्थ दण्ड/ दण्ड के सम्बन्ध में निर्णय	परिवहन, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन	आर0टी0ओ0, पुलिस अधीक्षक (यातायात), जिला मजिस्ट्रेट	
5.	अन्य आवश्यक निर्णयों के लिए टास्क फोर्स का गठन	वायु प्रदूषण के प्रति अतिसंवेदनशील समूह यथा वृद्ध, बच्चे एवं रोग ग्रस्त नागरिकों के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु टास्क फोर्स का गठन	जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

ब) निर्धारित एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	दिल्ली की सीमा में भारवाहक वाहनों का प्रवेश रोका जाना (आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त)	ट्रेफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग के कार्मिकों की प्रत्यावर्तन स्थलों पर तैनाती उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही	परिवहन विभाग, ट्रेफिक पुलिस	आर0टी0ओ0, पुलिस अधीक्षक (यातायात)	
2.	निर्माण कार्यों को बन्द करया जाना	बन्दी आदेश/नोटिस निर्माण स्थलों का निरीक्षण उल्लंघन पर कार्यवाही	आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास, नगर विकास, लो0नि0वि0	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आर0टी0ओ0, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0	
3.	ऑड/ईवन सिस्टम लागू किया जाना	सार्वजनिक यातायात सुविधा का विस्तार कार पूलिंग उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही	परिवहन, यातायात पुलिस, पुलिस	जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0, पुलिस अधीक्षक (यातायात), पुलिस अधीक्षक	
4.	टास्क फोर्स द्वारा अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना	प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से नोटिस/एडवाइजरी निर्गत करना मास्क वितरण स्कूल एवं चिकित्सालयों में अतिरिक्त सुविधा	जिला प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी	

2. Severe (PM_{2.5} 250 µg/m³ से अथवा PM₁₀ 430 µg/m³ से अधिक होने की स्थिति)

अ) पूर्व तैयारी के एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	ईट-भट्टों एवं हॉट मिक्स प्लान्ट का चिन्हीकरण	फील्ड सर्वे एवं सूची तैयार करना	जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लो0नि0वि0, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भू-तत्व एवं खनिकर्म	जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0, खनन अधिकारी, परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	
2.	सार्वजनिक यातायात हेतु बस / मेट्रो की आवृत्ति एवं संख्या बढ़ाना	अतिरिक्त कोच / बसों की उपलब्धता की प्लानिंग अतिरिक्त कर्मियों की उपलब्धता का नियोजन	जिला प्रशासन, परिवहन	जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0, क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम	
3.	सार्वजनिक यातायात में ऑफ पीक अवधि हेतु किराये का निर्धारण	सार्वजनिक यातायात में ऑफ पीक अवधि हेतु किराये का निर्धारण	परिवहन, गृह	परिवहन आयुक्त, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम, क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, आर0टी0ओ0, जिलाधिकारी	
4.	यात्रिक सफाई एवं जल छिड़काव हेतु अतिरिक्त मशीनों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु नियोजन / क्य	यात्रिक सफाई एवं जल छिड़काव हेतु अतिरिक्त मशीनों एवं मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु नियोजन / क्य	औद्योगिक विकास, नगर विकास	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा / ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त	
5.	कच्चे रास्तों का चिन्हीकरण	फील्ड सर्वे एवं चिन्हीकरण	औद्योगिक विकास, नगर विकास, लो0नि0वि0	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा / ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0	

ब) निर्धारित एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	ईट-भट्टों एवं हॉट मिक्स प्लान्टों को बन्द कराया जाना	बन्दी आदेश प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नोटिस उत्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही	जिला प्रशासन, पुलिस, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लो०नि०वि०, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग	जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशाषी अभियन्ता, लो०नि०वि०, खनन अधिकारी	
2.	सार्वजनिक यातायात सुविधाओं को बढ़ाना एवं ऑफ पीक किराया दरों को लागू करना	बसों/मेट्रो की संख्या एवं आवृत्ति बढ़ाना ऑफ पीक किराया दर लागू करना	परिवहन, जिला प्रशासन, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	जिलाधिकारी, आर०टी०ओ०, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	
3.	यांत्रिक सफाई को बढ़ाना एवं धूल उत्पन्न करने वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव करना	यांत्रिक सफाई को बढ़ाना एवं धूल उत्पन्न करने वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव करना	औद्योगिक विकास, नगर विकास, लो०नि०वि०, आवास एवं शहरी नियोजन	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, लो०नि०वि०, अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	
4.	प्राकृतिक गैस आधारित तापीय परियोजना में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना	प्राकृतिक गैस आधारित तापीय परियोजना में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना	एन०टी०पी०सी०, दादरी	महाप्रबन्धक, एन०टी०पी०सी०, दादरी	

3. Very Poor ($PM_{2.5}$ 121 से 250 $\mu g/m^3$ के मध्य अथवा PM_{10} 351 से 430 $\mu g/m^3$ के मध्य होने की स्थिति)
 अ) पूर्व तैयारी के एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	औद्योगिक/व्यवसायिक डीजल जेनरेटर सेट का चिन्हीकरण	सर्व एवं सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक सेवाओं हेतु प्रतिबन्ध से मुक्त रखे जाने हेतु चिन्हीकरण	जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
2.	पार्किंग फीस दरों का स्थल व समय के अनुसार निर्धारण	अत्यधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों एवं समय का चिन्हीकरण पार्किंग फीस में बढ़ोतरी कर निर्धारण	औद्योगिक विकास, नगर विकास, ट्रैफिक पुलिस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक (यातायात)	
3.	सार्वजनिक यातायात हेतु बस/मेट्रो की आवृत्ति एवं संख्या बढ़ाना	अतिरिक्त कोच/बसों की उपलब्धता की प्लानिंग अतिरिक्त कर्मियों की उपलब्धता का नियोजन	जिला प्रशासन, परिवहन	जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0, क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम	
4.	कोयला/जलावन लकड़ी का प्रयोग करने वाले होटलों/ढाबों का चिन्हीकरण	फील्ड सर्वे व सूचीबद्ध किया जाना	नगर विकास, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

ब) निर्धारित एक्शन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	डीजल जेनरेटर सेट का प्रचालन बन्द कराया जाना	बन्दी आदेश निर्गत उल्लंघनकर्ता पर कार्यवाही	जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
2.	पार्किंग फीस में बढ़ोत्तरी को लागू करना	आदेश निर्गतीकरण प्रचार प्रसार अवैध पार्किंग पर कार्यवाही	नगर विकास, औद्योगिक विकास, ट्रैफिक पुलिस	नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, पुलिस अधीक्षक (यातायात)	
3.	सार्वजनिक यातायात सुविधाओं को बढ़ाना एवं ऑफ पीक किराया दरों को लागू करना	बसों/मेट्रो की संख्या एवं आवृत्ति बढ़ाना ऑफ पीक किराया दर लागू करना	परिवहन, जिला प्रशासन, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	जिलाधिकारी, आर0टी0ओ0, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन	
4.	होटलों एवं ढाबों पर कोयला/जलावन लकड़ी का प्रयोग रोकना	बन्दी आदेश फ़ील्ड निरीक्षण एवं उल्लंघनकर्ता पर कार्यवाही	जिला प्रशासन, नगर विकास	जिलाधिकारी, नगर आयुक्त	
5.	आवासीय कल्याण सोसायटी द्वारा शीतकाल में सुरक्षा कर्मियों को हीटर इत्यादि उपलब्ध कराना	अपील/निर्देश निर्गत करना	आवासीय कल्याण सोसायटी, नगर विकास, औद्योगिक विकास	आवासीय कल्याण सोसायटी, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा	
6.	समाचार पत्र/टीवी0/रेडियो के माध्यम से जनसामान्य को सीमित आवागमन हेतु एडवाइजरी/अपील निर्गत करना	एडवाइजरी/अपील का प्रकाशन	जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ ग्रेटर नोयडा, मुख्य चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

4. **Moderate to poor** (Poor - PM_{2.5} 91 से 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ अथवा PM₁₀ 251 से 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य होने की स्थिति, Moderate - PM_{2.5} 61 से 90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ अथवा PM₁₀ 101 से 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ के मध्य होने की स्थिति)

अ) पूर्व तैयारी के एकशन बिन्दु एवं कृत कार्यवाही

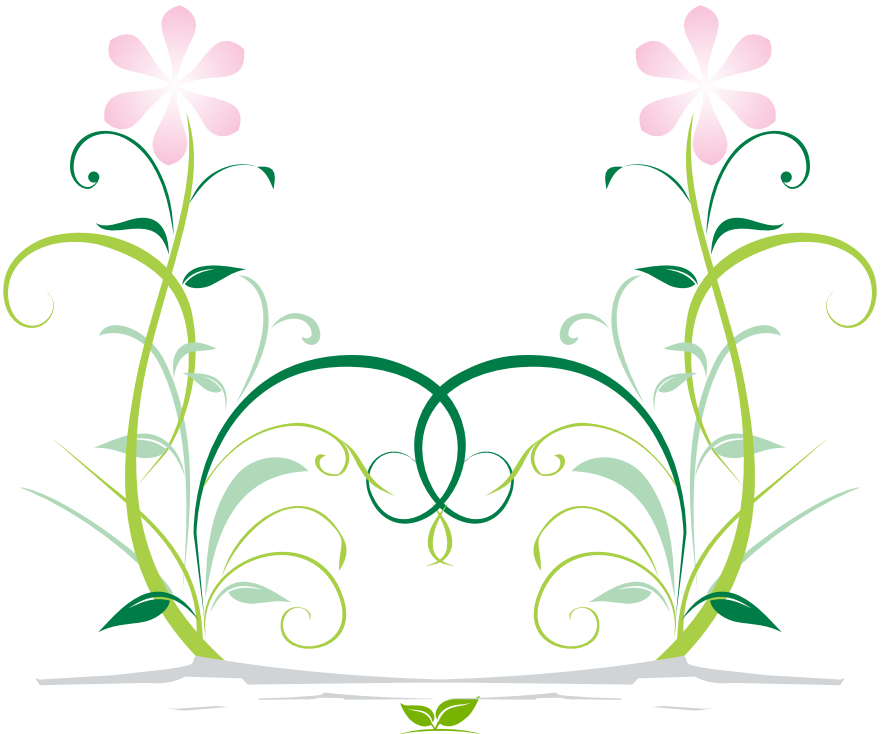
क्र.सं.	एकशन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
1.	लैण्डफिल साइट्स में कूड़ा जलाये जाने को कड़ाई से प्रतिबन्धित करना, भारी जुमना लगाना	फील्ड निरीक्षण एवं प्रवर्तन	औद्योगिक विकास, नगर विकास, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
2.	ईट-भट्टों एवं औद्योगिक ईकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों को कड़ाई से लागू करना एवं कार्यवाही करना	फील्ड निरीक्षण एवं प्रवर्तन	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन अधिकारी	
3.	तापीय विद्युत परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण मानकों को कड़ाई से लागू किया जाना	फील्ड निरीक्षण एवं प्रवर्तन	ऊर्जा, एनटी०पी०सी०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	महाप्रबन्धक, पावर प्लान्ट, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
4.	भारी यातायात वाली सड़कों पर आवर्ती यांत्रिक सफाई एवं कच्चे मार्गों पर दो दिन में एक बार जल छिड़काव किया जाना	यांत्रिक सफाई मशीन एवं टैंकरों का क्रय सफाई एवं छिड़काव की कार्यवाही	औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लो०नि०वि०	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	
5.	प्रत्यक्ष प्रदूषणकारी वाहनों की कड़ी निगरानी एवं कठोर कार्यवाही	प्रतिबन्धित करना भारी जुमना / सीजर की कार्यवाही	परिवहन, ट्रैफिक पुलिस	आर०टी०ओ०, पुलिस अधीक्षक (यातायात)	
6.	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणीकरण केन्द्रों की कड़ी निगरानी	निरीक्षण बन्दी एवं लाइसेंस निरस्तीकरण	परिवहन, ट्रैफिक पुलिस, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	आर०टी०ओ०, पुलिस अधीक्षक (यातायात), क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	

क्र.सं.	एक्शन बिन्दु	आवश्यक कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग	उत्तरदायी अधिकारी	कृत कार्यवाही
7.	निर्माण कार्यों में धूल नियंत्रण नियमों को कड़ाई से लागू करना।	फील्ड निरीक्षण बन्दी/जुर्माना की कार्यवाही	औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लो0नि0वि0	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा, नगर आयुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, लो0नि0वि0 एवं अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	
8.	संवदनशील मार्गों पर यातायात पुलिस की तैनाती कर ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाना।	संवदनशील मार्गों पर यातायात पुलिस की तैनाती कर ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाना	ट्रैफिक पुलिस, पुलिस	पुलिस अधीक्षक (यातायात), पुलिस अधीक्षक	
9.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली से भिन्न गंतव्य के ट्रकों तथा वर्ष 2005 के पूर्व पंजीकृत ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश वजित किया जाना।	डायवर्जन रूट का चिन्हीकरण दूरी/गंतव्य साइनेज की स्थापना डायवर्जन प्वाइन्ट पर चेकिंग	परिवहन, ट्रैफिक पुलिस	आर0टी0ओ0, पुलिस अधीक्षक (यातायात)	
10.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों को प्रतिबन्धित करने के आदेश को कड़ाई से लागू करना।	उत्पाद इकाईयों को बन्द करना विक्रय लाइसेंस निरस्त करना जनजागरुकता।	जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन	जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन अधिकारी	
11.	ग्रीष्मकाल (मार्च-मई) में फ्लाई ऐश पॉन्ड में प्रत्येक दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाना।	ग्रीष्मकाल (मार्च-मई) में फ्लाई ऐश पॉन्ड में प्रत्येक दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाना	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन परिषद, एन0टी0पी0सी0	महाप्रबन्धक	
12.	जनसामान्य से प्रदूषण के कारकों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त किये जाने तथा उन्हें प्रदूषण स्तर व नियंत्रण कार्यों की जानकारी प्रदान करने हेतु तंत्र का विकास करना।	कंट्रोल रूम की स्थापना मोबाइल ऐप का विकास सोशल मीडिया का उपयोग जागरुकता शिविर का आयोजन	जिला प्रशासन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सूचना विभाग	जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी	



परिशिष्ट-2

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार की अधिसूचना
संख्या-107, दिनांक 12.01.2017





भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 107]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

का.श. 118(ब).—दिल्ली में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय रहा है तथा प्रदूषण स्तरों में लगातार हो रही वृद्धि के विशेष संदर्भ में इस समस्या के निराकरण के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है;

भारत सरकार द्वारा अंभीकृत राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एन्यूआई) के अनुसार विभिन्न स्तरों के वायु प्रदूषण के निदान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तारीख 25 नवम्बर, 2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और उपयुक्त उपाय प्रस्तुत किए गए थे जिनमें और उपायों का क्रिया बचा था;

और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के आदेश में केंद्रीय सरकार को निर्देश दिया कि वह ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की जांच करके पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त अधिसूचना जारी करे;

और जबकि मामले की जांच की गई है तथा उस पर विधिवत् विचार करने के बाद केंद्रीय सरकार यह उपयुक्त समझती है कि उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में एक उपाय के रूप में ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के कार्यान्वयन का कार्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'ईपीसीए' कहा गया है) को सौंपा जाए;



अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा तारीख 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 93 (अ) के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के अधीन स्थापित तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्गठित ईपीसीए को ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन का कार्य सौंपती हैं।

[फा. सं. क्यू-18011/13/2000-सीपीए]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

S.O. 118(E).—Whereas high level of air pollution in Delhi and National Capital Region of Delhi has been a matter of serious concern and requires urgent measures to address the issue, particularly with reference to episodic rises in pollution levels;

And whereas a Graded Response Action Plan and appropriate measure to address different levels of air pollution as per National Air Quality Index (AQI) adopted by Government of India was submitted by the Central Pollution Control Board on the 25th November, 2016 before the Hon'ble Supreme Court which was further modified;

And whereas the Hon'ble Supreme Court in its order dated the 2nd December, 2016 has directed the Central Government to examine the Graded Response Action Plan and issue appropriate notification under sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

And whereas the matter has been examined, and after due consideration the Central Government considers it appropriate to entrust the task of implementing the Graded Response Action Plan as a measure under sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) to the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (hereinafter referred to as 'EPCA') in compliance of the aforesaid orders;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby assigns the task of implementation of the Graded Response Action Plan to the EPCA established under sub-section (3) of section 3 of the said Act vide notification number S.O.93 (E), dated the 29th January, 1998 and re-constituted from time to time by the Central Government.

[F. No. Q-18011/13/2000-CPA]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Submission by Central Pollution Control Board, Delhi

Graded response action plan according to pollution levels in Delhi and NCR to inform public action and to take effective steps to combat public health emergencies

December 2, 2016

The Hon'ble Supreme Court in its order of November 10, 2016 directed framing and submission of graded response action plan for various categories of National Air Quality Index (AQI). It also directed Central Pollution Control Board (CPCB) to convene a meeting on November 19, 2016 to get the views and suggestions of petitioners and other respondents on such plan.

Accordingly, a meeting was convened on November 19, 2016 at CPCB. The minutes of the meeting along with suggestions made and list of participants is annexed. (Appendix- I) Prior to this meeting two more meetings were held with implementing and monitoring agencies on November 16 & 17, 2016, and their suggestions on proposed action plan were taken.

In the hearing of November 25, 2016, CPCB had presented the draft of graded responses to different levels of pollution. The Hon'ble Court has "handed over to the Counsel opposite and Sunita Narain, who is present in person, to enable her to look into the matter and suggest such improvements and changes as may be considered necessary and feasible." sought further assessment and refinement of the proposed graded measures for finalization. CPCB and Sunita Narain have carried out further consultation to improve the proposal.

The graded measures for each source have been framed according to the AQI categories. It also takes note of the broad health advisory for each level of AQI that was adopted by the Government of India along with the AQI (See Table 1 and 2). The analysis of the past air quality trend shows that Severe and Very Poor air quality is anticipated throughout the winter months of November to February and largely poor category

during the summer months of March to May (Appendix – II).

The proposal has been framed keeping in view the key pollution sources in Delhi and National Capital Region of Delhi (NCR). While major sources of pollution including vehicles, road dust, biomass burning, construction, power plants and industries remain continuous throughout all seasons, the episodic pollution from stubble burning, increase in biomass burning, etc. varies across seasons. During winter the relative share of vehicles, biomass burning, MSW burning, firecracker, stubble burning, construction, and secondary particles increase. During summer, the influence of road dust, fly ash, vehicles, biomass burning etc is high.

The proposed graded measure approach has considered all these aspects and includes appropriate measures for each level of pollution according to AQI.

Table 1: National Air Quality Index

AQI Category (Range)	PM ₁₀ 24-hr	PM _{2.5} 24-hr	NO ₂ 24-hr	O ₃ 8-hr	CO 8-hr (mg/m ³)	SO ₂ 24-hr	NH ₃ 24-hr	Pb 24-hr
Good (0-50)	0-50	0-30	0-40	0-50	0-1.0	0-40	0-200	0-0.5
Satisfactory (51-100)	51-100	31-60	41-80	51-100	1.1-2.0	41-80	201-400	0.5-1.0
Moderately polluted (101-200)	101-250	61-90	81-180	101-168	2.1- 10	81-380	401-800	1.1-2.0
Poor (201-300)	251-350	91-120	181-280	169-208	10-17	381-800	801-1200	2.1-3.0
Very poor (301-400)	351-430	121-250	281-400	209-748*	17-34	801-1600	1200-1800	3.1-3.5
Severe (401-500)	430+	250+	400+	748+*	34+	1600+	1800+	3.5+

Table 2: Likely Health Impacts

AQI	Associated Health Impacts
Good(0-50)	Minimal Impact
Satisfactory (51-100)	May cause minor breathing discomfort to sensitive people
Moderately polluted (101-200)	May cause breathing discomfort to the people with lung disease such as asthma and discomfort to people with heart disease, children and older adults
Poor (201-300)	May cause breathing discomfort to people on prolonged exposure and discomfort to people with heart disease
Very Poor (301-400)	May cause respiratory illness to the people on prolonged exposure. Effect may be more pronounced in people with lung and heart diseases
Severe (401-500)	May cause respiratory effects even on healthy people and serious health impacts on people with lung/heart diseases. The health impacts may be experienced even during light physical activity

Key elements of the graded measures according to the pollution levels

The compliance to various rules and regulations must be ensured throughout the year. Set of actions is to be implemented with greater vigour and stringency as preventive measures to avoid emergency, severe, and very poor air quality.

The actions are to be implemented in the entire NCR, except the action related to stubble burning which is to be implemented in the states of Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. For the purpose of the smog alert and pollution emergency action the data from the available monitoring grid in Delhi will be considered for action in the entire NCR as it is a common air shed.

All actions suggested for each category – moderate to poor, very poor, severe and emergency -- are cumulative and add up to the level of emergency. Necessary preparations, including identification of sources and action plan, should be ready at least four weeks and actions initiated at least two weeks in advance of anticipated critical pollution days.

While the worst category according to the AQI is “Severe”, which in case of $PM_{2.5}$ is 250 microgram per cubic meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) and above and in case of PM_{10} 401 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ and above, another grade of health emergency level is proposed to be considered for more stringent action. The threshold for this category will be 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for $PM_{2.5}$ and 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ for PM_{10} , which are five times the standards. This is also consistent with the directive of the National Green Tribunal.

The institutional arrangement for the implementation is also presented here. The Hon'ble NGT vide its order of November 10, 2016, has constituted the Central and State level monitoring committees. Accordingly, the following structure will be set up.

A Task Force will be set up at the central level comprising representatives of CPCB, MOE&CC, DPCC, concerned SPCBs, IMD, health experts and

other stakeholders. This Task Force will be set up and headed by CPCB. IMD will carry out forecasting and alert the Task Force. This Task Force will meet at least once a week or daily, if necessary during peak winter months of mid-October to mid-February, to review air quality status including weather and air quality forecast.

At the state level, each State Government in Delhi and NCR will set up Monitoring Committees under the Chairmanship of the Chief Secretary to oversee implementation, monitoring, and compliance with the graded response measures. The Central Committee, headed by the Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, will review and coordinate actions taken and direct enforcement by concerned States.

Control rooms will be set up in Delhi Pollution Control Committee and concerned State Pollution Control Boards, traffic police and municipal bodies of NCT Delhi and NCR towns, for public to report on non-compliance. A central control room for overall monitoring will also be set up in Central Pollution Control Board.

The information about air quality will be sent to concerned Chief Secretaries of NCR, who are heading the State level committees so that the graded response, as detailed below, is implemented and enforced. This information about air pollution levels and the response required will also be communicated by the CPCB-headed Task Force directly and through the State governments to public so that they are informed about protective steps recommended for them as well as the steps required to be taken by governments.

During air quality emergencies, the CPCB-headed Task Force will suggest additional special measures that may be required to quickly bring down the air pollution levels to desired levels. The suggestion of the Task Force will be communicated to concerned Chief Secretary heading the State level committee, to ensure implementation. The Task Force may also suggest local measures in pollution hotspots. For example, Anand Vihar in Delhi that always shows up as very polluted area will require a local

area plan in addition to the graded measure for the city. This information will also be communicated to the public, through public advertisements, installation of notice boards in different parts of the cities and other means by the respective State Governments. The pollution emergency measures will have to be implemented under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment Protection Act, 1986. In fact, earlier on December 29, 2015, the Action Plan to contain air pollution in Delhi and NCR was issued by the Central Pollution Control Board under the Section 18(1)(b) of the Air Act, 1981 and on November 1 and 2, 2016, under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986.

The Monitoring Committee at the State government level will ensure implementation under section 31(A) of the Air Act, 1981.

As air quality analysis shows that most of the days during winter, between October 15 and February 15, fall in the AQI categories of Very Poor and Severe, it is appropriate to implement the measures that have been proposed for the AQI categories of Severe and Very Poor all through the winter, to prevent occurrence of severe or emergency situations.

The CPCB-headed Task Force will monitor air quality levels carefully and if the situation persists in Emergency category for 48 hours or more, then action as required under emergency situations shall immediately be pressed into action through State level committees and various implementing agencies listed in the action plan. However, all efforts will be made to reduce the response time so that people's exposure to toxic pollutants is reduced. This requires advance warnings and stringent implementation of actions required to reduce pollution before Severe or Emergency Level is breached.

The graded measures have been proposed for actions by the implementing agencies as well as by public for controlling of air pollution and reduction of outdoor exposures to protect health.

Table 3: Graded Response Action Plan for reducing air pollution

The graded measures according to AQI are listed from public health emergency level to downward. The measures are cumulative. Emergency and Severe levels include cumulatively all other measures listed in the lower levels of AQI including Very Poor, Poor and Moderate. It is also clear that the actions listed in the poor category need to be implemented though out the year. But during months when weather conditions turn more adverse there is need for greater scrutiny on enforcement.

Severe + or Emergency	Agency responsible/Implementing
When PM _{2.5} levels cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ levels cross 500 µg/m ³ (5 times above the standard) and persist for 48 hours or more	Agency
Stop entry of truck traffic into Delhi (except essential commodities)	Municipal Corporations and Traffic Police of Delhi and NCR Towns
Stop construction activities	Delhi Pollution Control Committee/Municipal Corporations of Delhi and NCR towns
Introduce odd and even scheme for private vehicles based on license plate numbers and minimize exemptions	Secretary cum Commissioner of Transport Department, NCT of Delhi, and Transport Commissioners of NCR towns
Task Force to take decision on any additional steps including shutting of schools	
Severe	
When PM _{2.5} levels are above 250 µg/m ³ or	
PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³	
Close brick kilns, Hot Mix plants, Stone Crushers	Chairpersons Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control

	Boards of Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh
	Superintendent of Police and Deputy Commissioner of respective districts
Shut down Badarpur power plant and maximize generation of power from existing natural gas based plants to reduce operation of coal based power plants in the NCR.	Chairpersons Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh
Intensify public transport services. Introduce differential rates to encourage off-peak travel.	Secretary cum Commissioner of Transport Department, NCT of Delhi, and Transport Commissioners of NCR towns
	Chairperson, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)
	Chairpersons, State Transport Corporations
Increase frequency of mechanized cleaning of road and sprinkling of water on roads. Identify road stretches with high dust generation.	All road owning agencies including Municipal Corporations of NCT of Delhi and NCR towns, Public Works Departments and National Highway Authority of India
Very Poor	
When PM_{2.5} levels are between 121-250 µg/m³ or	
PM₁₀ levels are between 351-430 µg/m³	
Stop use of diesel generator sets	Chairpersons Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh
Enhance parking fee by 3-4 times	Municipal Commissioner
	Municipal Corporations of NCT of Delhi and NCR towns
Increase bus and metro services by augmenting contract buses and increasing frequency of service	Principal Secretary, Department of Transport of NCT of Delhi
	Delhi Transport Corporation (DTC)
	Delhi Integrated Multi-modal Transit System Ltd (DIMTS)
	Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)

	State Transport Corporations in NCR towns
Stop use of coal/firewood in hotels and open eateries	Municipal Corporations of NCT of Delhi and NCR towns
Residential Welfare Associations and individual house owners to provide electric heaters during winter to security staff to avoid open burning by them	Resident Welfare Associations
Alert in newspapers/TV/radio to advise people with respiratory and cardiac patients to avoid polluted areas and restrict outdoor movement.	Chairpersons, Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh
Moderate to poor	
Poor – When PM_{2.5} levels are between 91-120 µg/m³ or	
PM₁₀ levels are between 251-350 µg/m³	
Moderate – When PM_{2.5} is between 61-90 µg/m³ or	
PM₁₀ is between 101-250 µg/m³	
Stringently enforce/stop garbage burning in landfills and other places and impose heavy fines on person responsible	Municipal Commissioner Municipal corporations of Delhi and NCR towns
Close/stringently enforce all pollution control regulations in brick kilns and industries	Chairpersons, Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh
Stringently enforce pollution control in thermal power plants through PCB monitoring	Plant in-charge of power plants in NCR, and Delhi Pollution Control Committee and State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh
Do periodic mechanized sweeping on roads with heavy traffic and water sprinkling also on unpaved roads every two days	Municipal Commissioner, Municipal Corporations of NCT of Delhi and NCR towns Commissioners, Traffic Police of Delhi and NCR towns to identify roads with heavy traffic and provide information to

	respective Municipal Commissioners
	Chief Engineers of officers in charge of CPWD, PWD of Delhi and NCR towns to identify unpaved roads with heavy traffic and provide information to respective Municipal Commissioners
Strict vigilance and no tolerance for visible emissions – stop plying of visibly polluting vehicles by impounding or heavy fine.	Commissioner or Officer in Charge, Transport Department and Traffic Police of NCT Delhi and NCR towns
Strict vigilance and enforcement of PUC norms	
Stringently enforce rules for dust control in construction activities and close non-compliant sites	Commissioner or Officers in charge of Police Departments of Delhi and NCR towns
Deploy traffic police for smooth traffic flow at identified vulnerable areas	Commissioners Traffic Police of Delhi and NCR Towns
Strictly enforce Supreme Court order on diversion of non-destined truck traffic and	Municipal Corporations of NCT of Delhi and NCR towns
ensure only trucks registered after 2005 are allowed entry into Delhi	Traffic Police of NCT of Delhi and NCR towns
Strictly enforce Supreme Court ban on firecrackers	Chief Controller of Explosives
	Petroleum and Explosive Safety Organizations (PESO)
	Commissioner of Officer in charge of licensing in the police departments of Delhi and NCR
Ensure fly ash ponds* are watered every alternate day during summer months (March – May).	Plant in charge of Power Plants in Delhi and NCR towns
Information dissemination Social media, mobile Apps should be used to inform people about the pollution levels, contact details of control room, enable them to report polluting activities/sources to the	Chairpersons, Delhi Pollution Control Committee, State Pollution Control Boards of Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh

concerned authorities, and actions that will be taken by government based on the level of pollution.

Note: * IIT Kanpur Report finds high flyash in air during summer months. Therefore, action is necessary during this period. But long term action has to be removal of this source of pollution from Delhi and its vicinity through the reuse and removal of all flyash dumps.

Action to be taken by public

While the CPCB headed Task Force will use the AQI and health advisory to inform people about the dangers of exposure, people are also expected to take precautionary measures to protect themselves. Suggested actions by public is listed below:

Level according to Air quality index	Action
Very poor, severe and emergency	Those suffering from heart diseases, asthma, and other respiratory disease may consider avoiding undue and prolonged exposure
	Schools to suspend all outdoor activities and sport events during Severe and Very Poor conditions
	Report visible emissions from vehicles, industries, power plants, garbage burning, and other non compliances to the respective control rooms
	Do not use diesel and kerosene generators
	Maintain vehicles properly (PUC certificate, replace car air filter, maintain right tyre pressure)
	Minimize unnecessary travel, use public transport and avoid using private vehicles

The compliance with various rules, regulations and action plans including short, medium and long terms measures must be ensured throughout the year. Directions were issued by CPCB on December 29, 2015 to contain air pollution in Delhi and NCR that include 42 points action plan. Time bound strategy and action are needed to comply with these measures to prevent occurrence of emergency, severe and very poor air quality.

IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA FOR SEEKING SUGGESTIONS OF THE PETITIONERS & RESPONDENTS IN THE MATTER OF M.C. MEHTA V/S. UNION OF INDIA, MEETING HELD ON 19.11.2016 AT CPCB, DELHI

MINUTES OF THE MEETING

In pursuant to the order, dated 10/11/2016 of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Air Pollution in Delhi and NCR (M.C. Mehta Vs. UOI), a stakeholder meeting to discuss graded response to various air quality situations in NCR Delhi was convened in Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi on November 19, 2016. The meeting was chaired by Shri S.P. Singh Parihar, Chairman, CPCB, and attended by petitioners, representatives of concerned Government departments, and their counsel. List of participants is annexed.

The Chairman welcomed the participants. After brief round of introduction, a presentation on air quality scenario in Delhi was made by CPCB. The presentation covered information on air quality monitoring network, air pollution status including levels during recent episode of severe air quality, air quality index (AQI) categories and associated likely health impacts, and number of days in a month under various AQI categories for the past year. Initiating the discussion, the Chairman observed that information on sources and contribution are available, and on the basis of this a broad action plan is already in place and has been conveyed to the concerned regulatory and implementing agencies in December 2015. Subsequently, specific directions have been issued on the 29th October, 1st and 2nd November 2016 to concerned agencies in Delhi and NCR. Meetings were also held by Chairman CPCB on the 30th September, Secretary MoEFCC on the 4th November and the Hon'ble Minister on the 7th November 2016 with Delhi and NCR State governments for effective compliance with the directions. He also



observed that the air quality in Delhi is much inferior in winter months as compared to other months in the year. The recent episode of extremely high air pollution levels was unprecedented and resulted due to adverse weather conditions as also local and other factors in the NCR States.

However, recurrence of such an event in future cannot be ruled out. Therefore, it is necessary that an action plan is put in place to prevent recurrence of such situations in future. Hon'ble Supreme Court and Hon'ble National Green Tribunal (NGT) have also expressed serious concerns and have desired that an emergency/graded response action plan is prepared to deal with such events. The Hon'ble Supreme Court has directed that a meeting with the petitioners in this case may be held on the 19th November at 11 AM in CPCB office and their suggestions for actions to improve the air quality of Delhi and NCR may be taken and incorporated in the proposed graded response action plan.

The views expressed by the participants are summarized below :

Shri Panjawani, CPCB Counsel :

- ✔ CPCB and SPCBs should be strengthened, and creation of three separate divisions for investigation, surveillance and compliance may be considered.
- ✔ Pollution Control Boards be renamed as Environment Protection Agencies
- ✔ Restriction be imposed on licensing, manufacturing, wholesale, and use of fire crackers with high noise levels and emissions
- ✔ Promote use of cleaner fuel and green technologies in crematoria

Dr. Kamat, Indian Medical Association :

- ✔ Strengthen implementation mechanism

Shri R. P. Singh, General Manager, National Highway Authority of India:

- ✔ Decongest arterial roads linked with national highways
- ✔ Install way motion bridges for trucks carrying goods at entry points to Delhi
- ✔ Remove bottlenecks for seamless flow of traffic

Student & Co petitioner

- ✔ Restrictions be imposed on manufacture and sale of fire crackers
- ✔ Sprinkle water on MSW dumping sites to suppress gaseous emissions
- ✔ Implement waste management practices

Shri Arun Shah, Co-petitioner

- ✔ Adopt sectoral approach for controlling pollution – actions for each sectors such as construction, firecracker, disposal of debris, etc
- ✔ Ensure shouldering of roads & vacuum cleaning
- ✔ Invite open suggestions for innovative approaches to deal with stubble burning
- ✔ Appeal to Residential Welfare Associations to provide electric heaters during winter to the Security Staff to discourage open burning by them

Ms. Asavi, student & co-petitioner

- ✔ Spread awareness among children about harmful effects of firecrackers
- ✔ Seek suggestions from school & college students on measures to reduce pollution
- ✔ Ensure better monitoring and repairing of potholes for improving flow of traffic and reducing pollution
- ✔ Spread awareness on environmental laws among public

Dr Ramesh Kumar, Chief Medical Officer, NDMC

- ✔ Strengthen mechanism for implementation and take punitive action where necessary
- ✔ Encourage use of compost pits in public and residential gardens
- ✔ Integrate multimodal transport system to facilitate use of public transport
- ✔ Enhance use of mechanical sweepers to contain dust related pollution
- ✔ Encourage multi-level parking.

Transport Department

- ✔ Encourage sensor based probe for PUC measurements
- ✔ Encourage installation of particulate filters in diesel vehicles
- ✔ Mandate that all States/UTs ensure pollution check for vehicles registered in their jurisdiction
- ✔ Strengthen Public transport

Shri Rally, Counsel, DPCC

- ✔ Spread awareness about severe health impacts of air pollution, particularly among school and college students in language that is simple to understand
- ✔ Publicize DOs and DONTs and the role of citizens
- ✔ Ensure installation of more air quality monitoring stations in Delhi

Assistant Commissioner of Police, Delhi

- ✔ States of Haryana & Uttar Pradesh to provide alternate routes for non-destined vehicles
- ✔ Adequate U-turns to be provided by the PWD of Delhi for returning non-destined vehicles
- ✔ Lay down a Policy for scrapping old and impounded vehicles in Delhi
- ✔ Carry out a comprehensive study on road bearing capacity in Delhi
- ✔ Link purchase of vehicles with availability of parking space
- ✔ Public transport be made reliable, robust, and efficient
- ✔ Encourage multilevel parking.

Haryana SPCB

- ✔ Ensure alternate power supply arrangements in the event of shutting down Thermal Power Plants, as it may increase use of DG sets.
- ✔ Ban use of firecrackers during marriage functions
- ✔ Stop manufacture of firecrackers for five years
- ✔ Promote alternate use of Wheat/Paddy stock to prevent stubble burning
- ✔ Re-circulate leachate in landfill sites to contain Methane and extinguish fire at such sites

Shri Aniruddh Suri, Co-petitioner

- ✔ Technology and data from Google may be used to address issues related to traffic decongestion
- ✔ Impose complete ban on manufacture, sale and use of firecrackers, as it has no socio-economic benefits
- ✔ Ensure wide publicity of Air Quality Index using display boards across the city
- ✔ Ensure strict action against non-performers in government agencies
- ✔ Work out localized solutions to control air pollution and promote use of Ethanol in auto fuel
- ✔ For prevention of stubble burning, farmers should be sensitized that it not only affects health but also causes financial loss due to decline in soil fertility
- ✔ Encourage cooperation with agencies like USEPA and others for innovative solutions
- ✔ Do not permit a Polluting vehicle to ply even if it is being used to carry essential goods
- ✔ Undertake indigenous scientific studies on air pollution and health impacts
- ✔ Popularize mobile apps on various aspects of air pollution and CPCB to further improve its website to provide uninterrupted information
- ✔ Engage with citizens more closely to seek suggestions for actions to control pollution.
- ✔ Action plan to indicate clearly the agencies and officers responsible for various activities and the plan be placed in public domain so that public can directly approach those responsible and hold them accountable

Dr Sarath Pallerla, Director, MoEF&CC

- For implementation of graded response there is a need to expand infrastructure, enhance manpower and augment funding
- Prepare specific action plan for festivals like Diwali

U.P. SPCB

- Directions of Pollution Control Boards are not being implemented specially by government agencies such as development Authorities and ULBs
- Mechanism for coordinated response at the State Government level be put in place

Summary:

Summarizing the discussions, the Chairman, CPCB thanked the participants for their valuable suggestions and observed that the suggestions will be appropriately incorporated in the draft graded response action plan which is being prepared for submission to the Hon'ble Supreme Court. It was agreed that in order to prevent recurrence of higher levels of pollution it is important to sensitize public in general and school/college students in particular. For effective implementation of action plans, Public agencies will have to be better equipped and made more accountable. It was further agreed that government agencies such as CPCB and others should engage with public more closely to invite their suggestions for effective check on pollution as only a joint and concerted action can bring in meaningful solution to the recurrent problem of air pollution in Delhi and NCR.

The participants were then requested to visit the Air Laboratory, Central Data Monitoring Facility and Air Quality Monitoring Station established on the campus of CPCB.

The meeting ended with thanks.

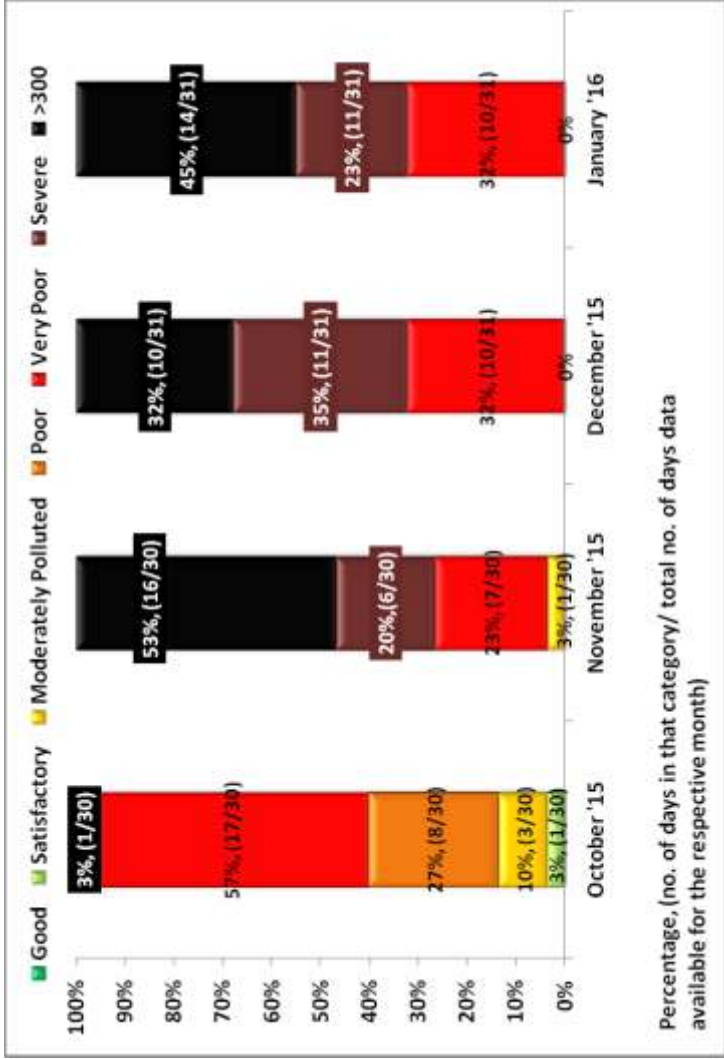
List of Participants

Sl.No.	Name of the Person	Designation	Organization	Mobile/Phone No.	E-Mail
1	Shri S.P.S Parihar	Chairman	CPCB		
2	Dr. A.B. Akolkar	Member Secretary	CPCB		
3	Shri Arun Shah	Ex. Director	Delhi Association of the Deaf	9810608085	arunshah100@yahoo.com
4	Dr. Sanjeev Agrawal	Additional Director	CPCB	9891903524	sanjeevagrawal.cpcb@gmail.com
5	Miss Tarini Sharma	Student		8800762004	tarinisharma03@gmail.com
6	Miss Vasavi Broota	Student		9717109103	vasavibroota@gmail.com
7	Shri B.B Jindal	Manager(T)	NHAI	9810477354	ggv@nhai.org
8	Miss Bhavana Dahoon	Advocate	NHAI	7769040463	bhavanaduhoon@mvkini.com
9	Shri Vijay Panjwani	Advocate (CPCB)	CPCB	9818475018	panjwanivijay62@gmail.com
10	Dr. Vivek Kumar	D.C	Transport	9650705070	
11	Shri Arvinder Soni	Asst. (T)	Traffic Police	8750871415	soniravinder@gmail.com
12	Shri D.P Bhardwaj	AE	SDMC	9717788282	khanm1961@gmail.com
13	Shri O.P Gupta	R.O	RSPCB	9910419599	ro.alwar@gmail.com
14	Shri Sanjeev Ralli	Advocate	DPCC	9811087093	sanjeev@ralli.in
15	Dr. P.K.M.K Das	Sr Scientist	HSPCB	9810733523	drpkmkhspcb@gmail.com
16	Dr. M.P. George	Sc-D	DPCC	9717593520	mohanpg@gmail.com
17	Shri Parasrath	R.O	UPPCB Ghaziabad	7839891724	roghaziabad@uppcb.com
18	Dr. B.B Awasthi	R.O	UPPCB Noida	7839891745	ronoidea@uppcb.com
19	B.P Yadav	AEe	UPPCB Noida	7839891746	ronoidea@uppcb.com
20	Shri D.S Khatri	Consultant (s)	Delhi Cantt Board	07351111614	dskhatri1456@gmail.com
21	Shri M.S.Nagvi	AE	DEMS, NDMC	9717787694	murtazarshujenaqvi@gmail.com

22	Shri Arun Vesale	CSO	NDMC	9810545410	
23	Dr. Ramesh	CMO	NDMC	01123745323	
24	Dr. N.V. kamat	Principal Advisor	IMA	9810446260	hsg@ima-india.org
25	Shri V.K Saraswat	PLO	Transport Department(NCT)	704275573	vk Saraswat61@gmail.com
26	Shri Vivek Garg	Asstt. Architect	New Delhi Municipal Council	9811489930	gurucharan.avch@gmail.com
27	Shri V.R. Bansal	SE	North	9717787771	buildinghqcc@gmail.com
28	Shri Hemant Arya	Advocate	Supreme Court	8947707378	Hemantarya1910@gmail.com
29	Shri Arun Kumar	Se	EDMC	9717788001	arunkmcd@gmail.com
30	Shri Shikhil Suri	Advocate		9619690406	shikhilsuri@gmail.com
31	Shri Anirudh Suri	Petitioner In 899/2016 W.p. (C)	IIF	9910370732	anirudhsuri@gmail.com
32	Shri Ajay Nagpal	EE (B) HQ	NDMC	9717788489	ajaynagpal@gmail.com
33	Miss RekhaGiri	Advocate	Supreme Court	9013157041	adrekhaGiri@gmail.com
	For R.K. Kapoor				
34	Shri R.P. Singh	General Manager	NHAI	9650936940	gha@nhai.org
35	Dr.Parhant Gargav	AD	CPCB	9990870057	Eepg.cbcb@nic.in
36	Shri A.Sudhakar Addl.	Director	CPCB	8800326699	asudhakarcpcb@nic.in
37	Shri D. Saha	AD	CPCB	9717166653	dsaha.cpcb@nic.in
38	Shri Paras Nath	R.O	UPPCB Ghaziabad	9818922805	roghaziabad@uppcb.com
39	Dr.SharathKumarPallerla	Director MoEFCC	MoEFCC	9205319757	sharath.kr@gov.in
40	Shri Tarun Darbari	Scientist C	CPCB	9999969389	tarundarbari@gmail.com
41	Dr. Sanghita Roy chudhary	RA	CPCB	9871984779	rcsanghita@gmail.com
42	Miss Razia Sultan	DEO	CPCB	9650939647	sanjeevagrawal.cpcb@gmail.com

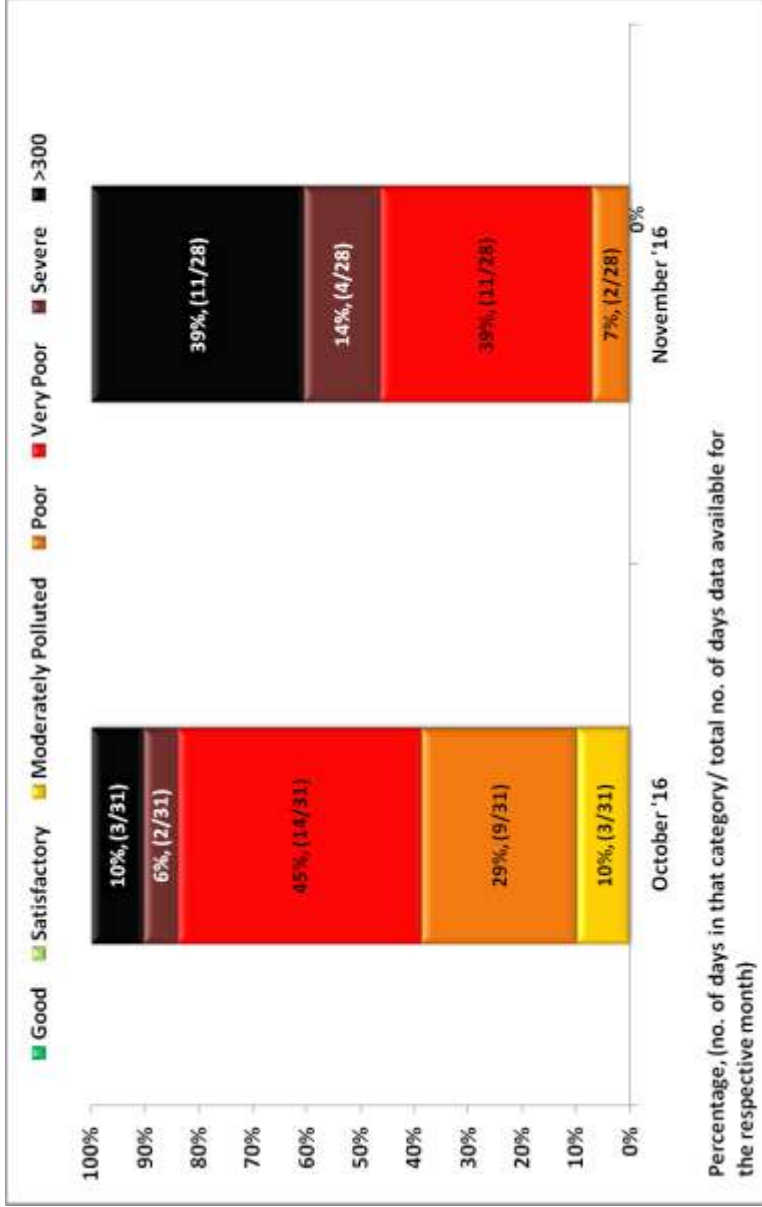
Appendix – II

Graph 1: Percentage share of days in different AQI categories (PM^{2.5} from October 2015 to January 2016)



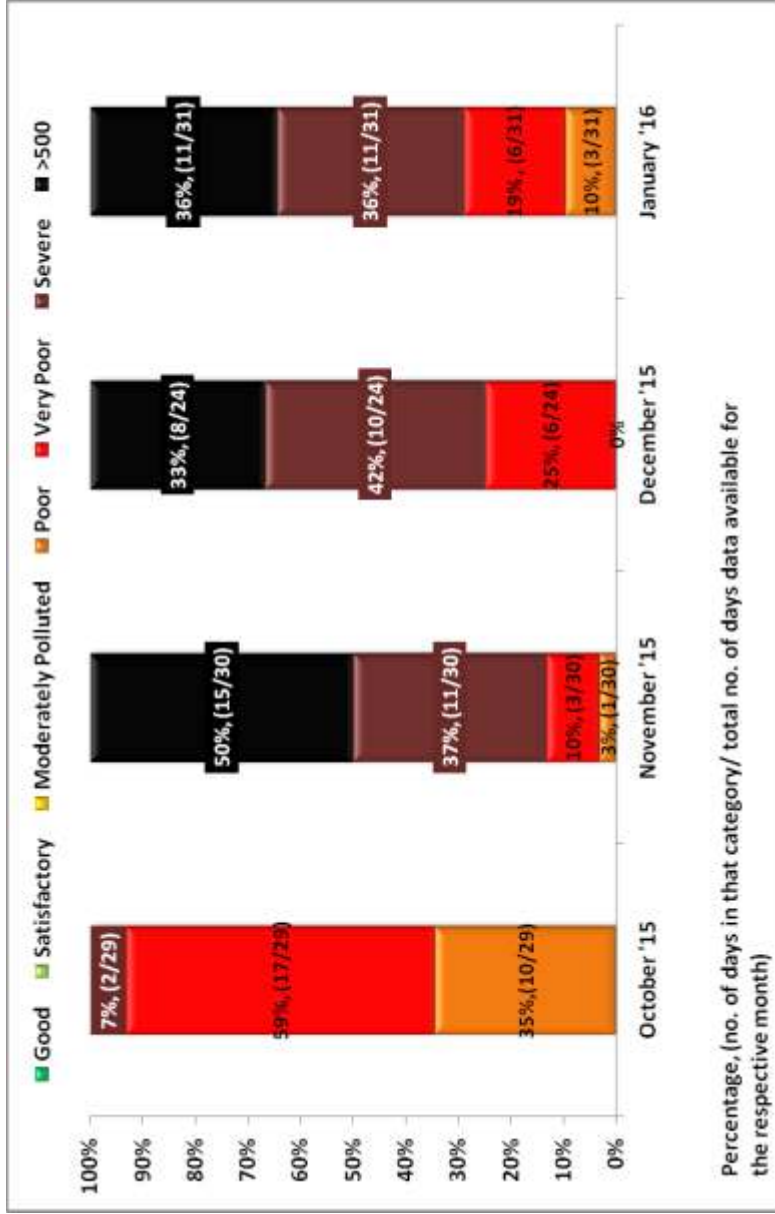
Source: Based on CPCB data

Graph 2: Percentage share of days in different AQI categories (PM^{2.5} from October- November 2016)



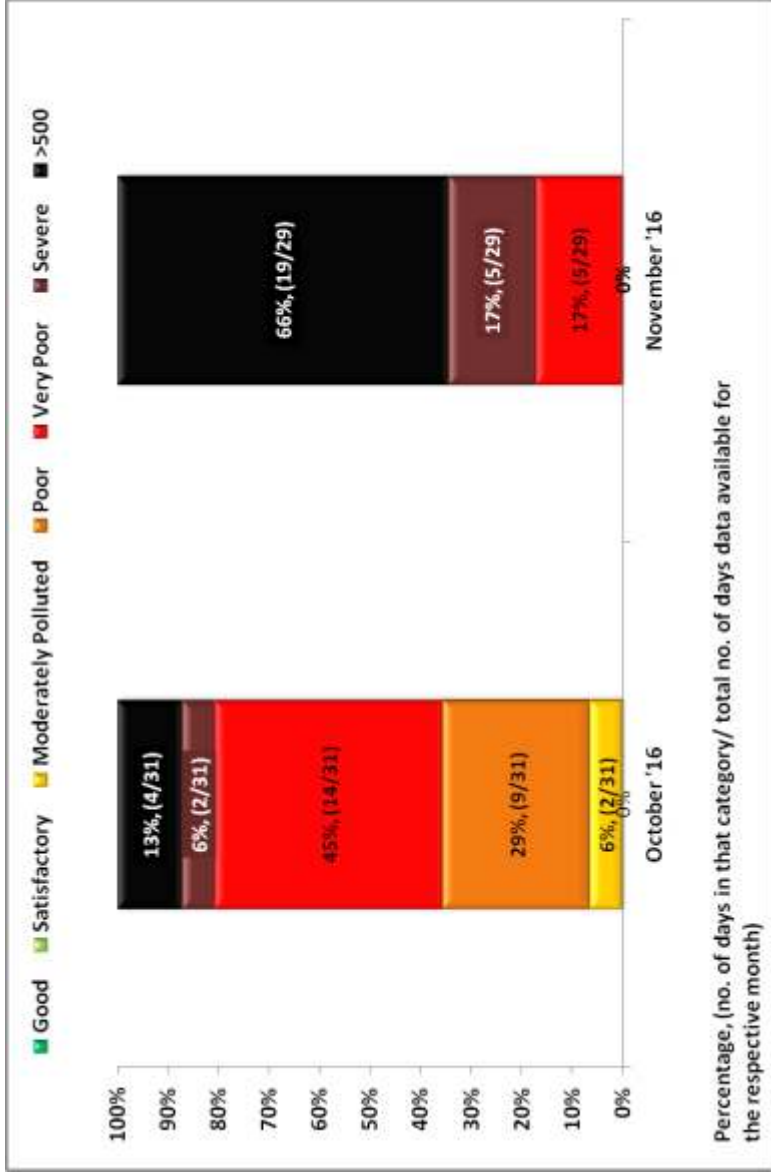
Source: Based on CPCB data

Graph 3: Percentage share of days in different AQI categories (PM¹⁰ from October 2015 to January 2016)



Source: Based on CPCB data

Graph 4: Percentage share of days in different AQI categories (PM¹⁰ from October- November 2016)



Source: Based on CPCB data



D.O. No. Q-18011/13/2000-CPA

Dated the 13th January, 2017

Dear Sir,

This refers to the directions passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P (C) No.13029 of 1985 of in the matter of M.C.Mehta Versus Union of India & Others wherein the Hon'ble Supreme Court has directed the Central Government to examine the Graded Response Action Plan to different levels of Air Pollution in NCR as proposed by Central Pollution Control Board and issue an appropriate notification under Section 3(1) of Environment (Protection) Act, 1986. The Hon'ble Supreme Court had further directed that the implementation of the Graded Response Action Plan shall be under the orders of Environmental Pollution Control Authority (EPCA).

2. In pursuance of aforesaid direction, the MoEF&CC has issued the notification entrusting the implementation of Graded Response Action Plan to the EPCA. A copy of relevant notification dated 12.01.2017 is enclosed.

3. As directed by the Hon'ble Supreme Court, the MoEF&CC has further examined the Graded Response Action Plan with you and the concerned State Governments in a meeting held on 10th January, 2017. A copy of the minutes of the meeting is being sent separately. It is noted that the following decisions were taken in the meeting:

- i) The air quality index for implementation of Graded Response Action Plan should be based on the readings of at least 50% of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS). Currently there are 20 CAAQMS in Delhi comprising 6 monitoring stations of CPCB, 6 of DPCC and 8 of SAFAR. In future, the number shall become larger as more stations are set up in the NCR and data from other stations are included.
- ii) The Graded Response Action Plan should be seen as an evolving plan. Beginning may be made with Graded Response Action Plan as submitted before the Hon'ble Supreme Court with exemptions with respect to use of diesel generators for emergency services like hospitals, lifts etc. However, as more experience is gained in its implementation, it may be suitably calibrated and the Hon'ble Supreme Court, be apprised accordingly.
- iii) A task force headed by CPCB was constituted comprising Members Secretaries of CPCB, State Pollution Control Boards of NCR & Punjab and DPCC apart from representative of IMD, Health Experts and experts in matters relating to air pollution. Every attempt should be made to ensure that decisions of task force are taken with a minimal quorum.



तीसरा तल, पृथ्वी विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110 003
फोन : 011-24695456, फ़ैक्स : 011-24695455, ई-मेल : akmehta@nic.in

Room No. 320, 3rd Floor, Prithvi Wing, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003
Phone : 011-24265456, Fax : 011-24695455, E-mail : akmehta@nic.in

- iv) The mandate of the task force should include consideration of various measures required to different levels of AQI for appropriate recommendations to EPCA.
 - v) Since the task force will be required to meet very frequently during periods of poor air quality, it was decided that task force may evolve suitable methods for its meetings including tele-conferencing / video conferencing etc.
 - vi) Attempts shall be made that meetings of EPCA are attended by all the members and minimal quorum is maintained without compromising on the decision making during the situations requiring urgent attention.
4. The Graded Response Action Plan as submitted before the Hon'ble Supreme Court is hereby conveyed to you under section 3(1) of the Environment (Protection) Act, 1986 with a request to ensure implementation of the plan, keeping in view the decisions taken in the meeting held on 10.01.2017
5. It is further requested that steps may kindly be taken to apprise the Hon'ble Supreme Court and this Ministry regularly of the progress of implementation of the Action Plan.

With kind regards .

Yours Sincerely,

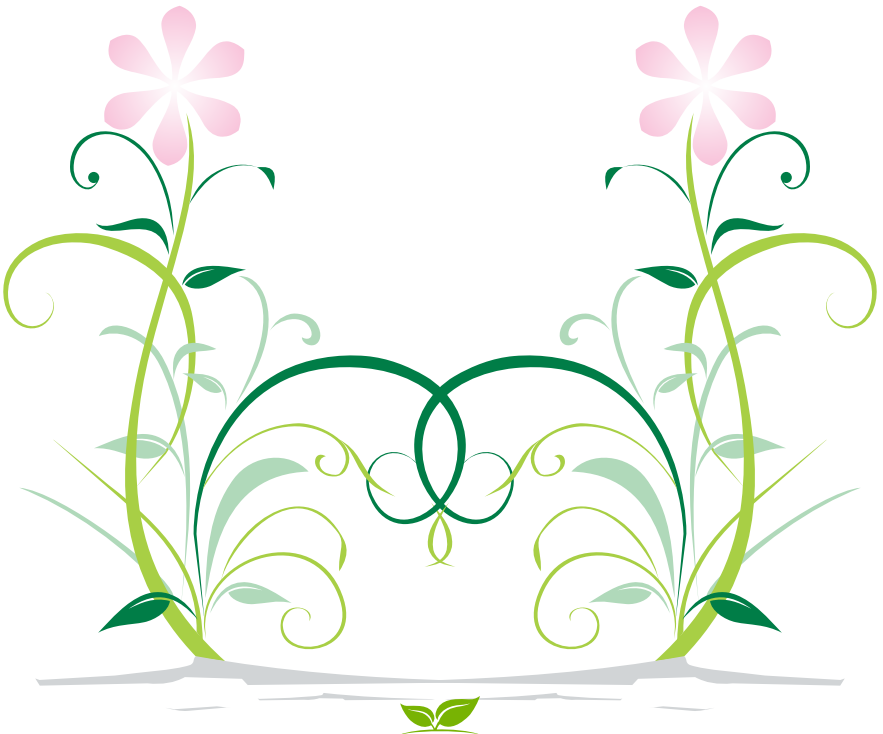

(Arun Kumar Mehta)

Shri Bhure Lal (Ex- Secretary, Govt. of India),
Chairman,
Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA),
Parivesh Bhavan,
East Arjun Nagar, Delhi-110032

Encl. : As Above

परिशिष्ट-3

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०
की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक
दिनांक 12.01.2017 का कार्यवृत्त



ओ०ए० संख्या-21/2014 बर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य तथा ओ०ए० संख्या-18/2013 विक्रान्त कुमार तौगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया में वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12-01-2017 का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

- 2- अपर मुख्य सचिव पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मामले में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व में बैठक दिनांक 23-11-2016 में यह निर्देश दिये गये थे कि सभी संबंधित विभाग विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये उसकी सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दें। उक्त आदेशों के अनुपालन में अभी तक कई विभाग जैसे आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पंचायती राज आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर उसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि जिन विभागों द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है उनके द्वारा तत्काल नोडल अधिकारी नामित कर उसकी सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित बैठकों में भविष्य में विभागीय नोडल अधिकारी ही बैठक में प्रतिभाग करें ताकि मा० अधिकरण के आदेशों के अनुपालन से संबंधित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श में निरन्तरता बनी रहे।

(कार्यवाही सभी संबंधित विभाग)

- 3- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रश्नगत वादों की प्रभावी पैरवी हेतु श्री पिनाकी मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता को आबद्ध किया गया है। सभी संबंधित विभागों यथा आवास एवं शहरी नियोजन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, कृषि, परिवहन एवं गृह विभाग सहित महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-3517/55-पर्या-2016-09(रिट)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा अवगत करा दिया गया है कि अपने से संबन्धित बिन्दुओं पर समस्त सूचनार्थ/विवरण सहित श्री पिनाकी मिश्रा से सम्पर्क कर उन्हें ब्रीफ करें। प्रश्नगत वादों में राज्य सरकार का पक्ष मा०



अधिकरण में समेकित रूप से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित विभाग अपना विभागीय पक्ष उक्तानुसार नामित वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से मा० अधिकरण में प्रस्तुत किया जाये। श्री पिनाकी मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता का ई-मेल pinakimisra@gmail.com है।

- 4- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मामले में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों को संकलित करते हुये विभागवार टेम्पलेट तैयार किया गया है। इसी टेम्पलेट पर सभी संबंधित विभागों द्वारा मा० अधिकरण के आदेशों के संदर्भ में बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जानी है। निर्देशित किया गया कि उक्त टेम्पलेट की प्रति पुनः सभी संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी जाय जिसपर उनके द्वारा साफ्ट एवं हार्ड कापी में प्रत्येक दशा में दिनांक 16-01-2017 तक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके ई-मेल (info@uppcb.com) एवं पर्यावरण अनुभाग के ई-मेल (soenvups@rediffmail.com) पर अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायी जाय। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना में कृत कार्यवाही से संबंधित सुसंगत आंकड़ों का समावेश करते हुये विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित कर ली जाय।

(कार्यवाही पर्यावरण विभाग/सभी संबंधित विभाग)

- 5- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि एन०सी०आर० क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित मा० उच्चतम न्यायालय में योजित वाद में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान को मा० न्यायालय द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्र में लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं। वायु प्रदूषण के अनुरूप रिस्पान्स योजना लागू किया जाना है। उक्त प्लान को संबंधित विभागों को परिचालित कर दिया गया है। यह भी अवगत कराया कि अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो वायु प्रदूषण स्तर के सम्बन्ध में मानीटरिंग करेगी व इसका स्तर एन०सी०आर से सम्बन्धित राज्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेगी। वायु प्रदूषण का स्तर इमरजेन्सी व अन्य लेवल तक पहुंचने की दशा में प्लान के अनुसार सुसंगत कार्यवाही सम्बन्धित विभागों द्वारा की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि प्लान के जिन बिन्दुओं पर विभागों द्वारा कार्यवाही की जानी है उन विभागों को तत्काल चिन्हित कर लिया जाय। इस व्यवस्था के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्लान के अनुसार वांछित कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाय ताकि किसी आपातिक स्थिति में विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जा सके।

(कार्यवाही पर्यावरण एवं समस्त संबंधित विभाग)

- 6- एनसीआर क्षेत्र में वाहनों से जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं वाहनों का आवागमन कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क को बढ़ाया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

**(कार्यवाही नगर विकास/औद्योगिक विकास/आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग)**

- 7- एन०सी०आर० क्षेत्र विशेष रूप से नोयडा, ग्रेटर नोयडा व गाजियाबाद में सड़कों की पूर्णतया मेकेनाइज्ड स्वीपिंग की व्यवस्था नगर विकास विभाग व सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित की जाय।

**(कार्यवाही नगर विकास/औद्योगिक विकास/आवास
एवं शहरी नियोजन विभाग)**

- 8- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि डा० भूरेलाल की अध्यक्षता में गठित इन्वायरमेन्ट पाल्यूशन कन्ट्रोल अथारिटी (ई०पी०सी०ए०) द्वारा एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों द्वारा पेट-कोक व फर्नेस आयल का ईंधन के रूप में अधिक उपयोग किये जाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में निदेशित किया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा एनसीआर क्षेत्र में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये ताकि औद्योगिक/कामर्शियल/घरेलू प्रयोजनों में डी०जी० सेट के प्रयोग की आवश्यकता न पड़े और औद्योगिक इकाइयों में पेट-कोक व फर्नेस आयल के उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। ऊर्जा विभाग को यह भी निर्देश दिये कि एन०सी०आर० क्षेत्र में औद्योगिक एवं घरेलू फीडर में विद्युत आपूर्ति के माह नवम्बर 2016 से अब तक के आंकड़े पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराये जायें।

(कार्यवाही ऊर्जा विभाग/पर्यावरण विभाग)

- 9- ईपीसीए द्वारा लोनी सहारनपुर मार्ग को तात्कालिक रूप से सुदृढ़ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ताकि दिल्ली में वाहनों के अनावश्यक प्रवेश को रोका जा सके व केवल वही वाहन जिन्हें दिल्ली जाना है, प्रवेश कर सकें। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त के साथ अन्य संबंधित मार्गों के सुधार हेतु यथा प्रक्रिया टेण्डरिंग की कार्यवाही करा ली जाय।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग)

- 10-दिल्ली में वाहनों के प्रवेश के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जिन वाहनों का गन्तव्य दिल्ली न हो उन्हें दिल्ली की सीमा से कम से कम 3 किमी० पहले ही अन्य मार्गों से डायवर्ट किये जाने की व्यवस्था की जाये। यातायात के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था जैसे इलेक्ट्रॉनिक

साइनेज लगाये जाने आदि हेतु निर्देश दिये गये। साइनेज की डिजाइन व विषयवस्तु परिवहन विभाग को निदेशक, यातायात द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। परिवहन विभाग द्वारा रोड सेफ्टी फण्ड से उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। यह भी निदेशित किया गया कि वाहनों को डायवर्ट कराये जाने के आंकड़े निदेशक, यातायात द्वारा नियमित रूप से परिवहन विभाग को उपलब्ध कराये जाय जिसे परिवहन विभाग द्वारा अपनी अनुपालन आख्या में समावेशित किया जाये।

(कार्यवाही परिवहन विभाग/गृह विभाग/निदेशक यातायात)

11-एनसीआर क्षेत्र में पूर्व से ही यूरो-4 वाहनों की व्यवस्था लागू है। परिवहन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में औपचारिक सूचना पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

(कार्यवाही परिवहन विभाग/पर्यावरण विभाग)

12-यह भी अवगत कराया गया कि ईपीसीए द्वारा पुलिस व परिवहन विभाग को वाहनों की प्रदूषण जाँच किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यातायात पुलिस की ओर से अवगत कराया गया कि प्रदूषण जाँच का कार्य उनसे सम्बन्धित नहीं है। इस संबंध में परिवहन विभाग को निर्देश दिये गये कि एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की पीयूसी चेकिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा चेकिंग/चालान किये गये वाहनों की माहवार संख्या एवं इस संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना का समावेश परिवहन विभाग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट में किया जाये।

(कार्यवाही परिवहन विभाग/निदेशक, यातायात)

13-अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि ईपीसीए द्वारा दिनांक 10-01-2017 की बैठक में दादरी पावर प्लान्ट के पूर्ण क्षमता पर कार्य न किये जाने व इस कारण एनसीआर क्षेत्र में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था न होने का बिन्दु उठाया गया। इस सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दादरी पावर प्लान्ट एनटीपीसी द्वारा संचालित है। साथ ही इस प्लान्ट द्वारा दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति का मूल्य अधिक होने के कारण इस प्लान्ट से आपूर्ति नहीं ली जा रही है। ऊर्जा विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस प्लान्ट से आपूर्ति प्राप्त न किये जाने का एनसीआर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्जा विभाग को निदेशित किया गया कि इस सम्बन्ध में एक औपचारिक स्टेटस रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही ऊर्जा विभाग/पर्यावरण विभाग)

14-थर्मल पावर स्टेशनों से जनित फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों को मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी टेण्डर उनके द्वारा जारी किये जायें उनमें 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश का प्रयोग किये जाने की शर्त रखी जाये। मा० राष्ट्रीय हरित

अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में थर्मल पावर स्टेशन से 300 किमी० के क्षेत्र में फ्लाई ऐश सफ़ाई करने का व्यय भार सम्बन्धित थर्मल पावर स्टेशन द्वारा ही किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा ऊर्जा विभाग को निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में आने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन कर उपलब्ध कराया जाये। मामले में वांछित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करायी जाय।

**(कार्यवाही लोक निर्माण/ऊर्जा/आवास एवं
शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)**

- 15-ईपीसीए द्वारा एनसीआर क्षेत्र में विशेष कर नोयडा, ग्रेटर नोयडा व गाजियाबाद में कूड़े के जलाये जाने पर पूर्णतया रोक लगाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग व औद्योगिक विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने व स्टेटस प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही नगर विकास/औद्योगिक विकास विभाग)

- 16-ईपीसीए द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि डीएनडी पर माल वाहक वाहनों हेतु आरएफआईडी चेक पोस्ट को अग्रिम आदेशों तक बनाये रखा जाये। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग को निर्देश दिये गये कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही परिवहन विभाग)

बैठक के अन्त में पुनः समस्त को निर्देशित किया गया कि मा० अधिकरण के आदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाय और यदि किसी कारणवश अनुपालन किये जाने में विलम्ब हो रहा हो या किसी बिन्दु पर निर्णय प्रक्रियाधीन हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख टैम्पलेट के अन्तिम स्तम्भ में किया जाय। प्रस्तुत आख्या में आंकड़े सुस्पष्ट एवं तथ्यपरक हों। मात्र निर्देश निर्गत करना आदेशों का अनुपालन नहीं माना जायेगा। मा० अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 10-11-2016 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि केन्द्रीय समिति द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी संवर्ग/अथारिटी के किसी अधिकारी द्वारा वायु प्रदूषण रोके जाने से संबंधित मा० अधिकरण के आदेशों/निर्णयों/निर्देशों तथा नियमों आदि का अनुपालन न किये जाने के संबंध में उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी। उक्त के दृष्टिगत पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित विभागों द्वारा मा० अधिकरण के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्तानुसार वांछित आख्या तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

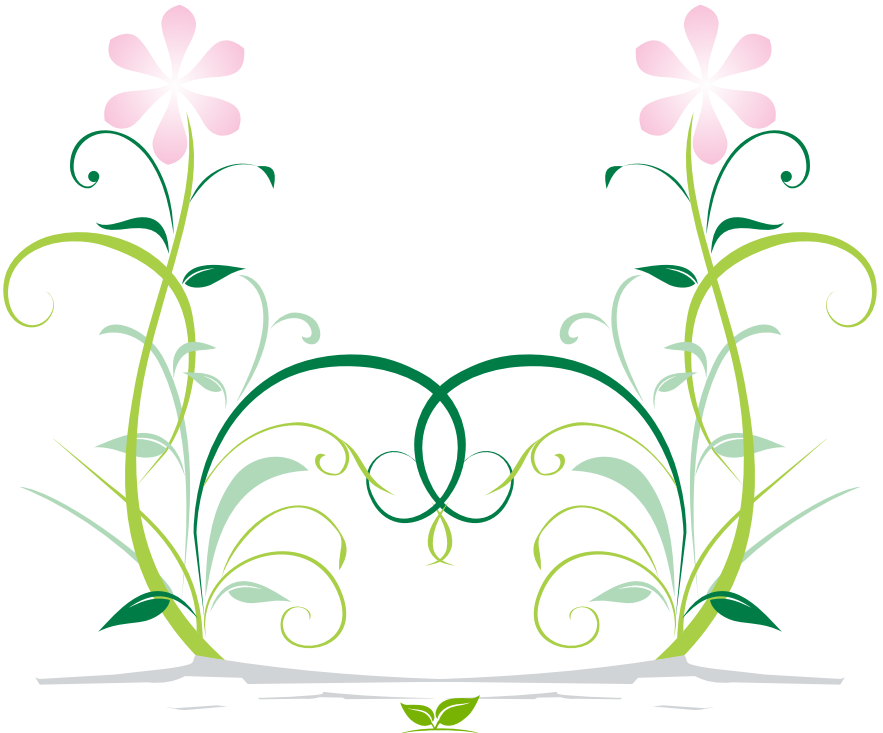
(कार्यवाही समस्त संबंधित विभाग)

उक्त के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

मुख्य सचिव,
उ० प्र० शासन।

परिशिष्ट-4

ग्रेडिड रिस्पॉंस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन हेतु
EPCA द्वारा आयोजित बैठक
दिनांक 20.01.2017 का कार्यवृत्त



Minutes of the Meeting of Environment Pollution (Prevention & Control) Authority for the NCR (EPCA) held on January 20, 2017 (Friday) at 3.45 pm

(at Chairman, EPCA office at MCD Supreme Court Monitoring Committee, 3rd Floor, Core VI, IHC, Lodi Road, New Delhi)

Agenda: 'Graded Response Action Plan' to combat air pollution situations according to pollution levels in Delhi and NCR

Attendance :

Chairman and Members EPCA

1. Dr. Bhure Lal, Chairman, EPCA
2. Ms. Sunita Narain, Member, EPCA
3. Mr. Chandraker Bharti, Secretary Environment, Delhi Government
4. Dr. A. B. Akolkar, Member EPCA

Substitutes of EPCA members or officers accompanying

EPCA Members

5. Dr. Vivek Kumar, Transport Department Delhi
6. Mr. Dilip Ramnani, CE, SDMC
7. Dr. Dipankar Saha, Sc. E, CPCB
8. Mr. A. Sudhakar, Sc. E, CPCB
9. Nazimuddin, Sc. E, CPCB

Representatives of other concerned agencies

U.P.

10. Mr. Sanjiv Saran, Additional Chief Secretary - Environment, U.P. Government
11. Mr. Ashish Tiwari, Special Secretary- Environment, U.P. Government
12. Dr. Rajeev Upadhyay, Chief Environmental Officer, UPPCB

Haryana

13. Mr. S. Narayanan, MS, HSPCB

Rajasthan

14. Dr. Vijay Singhal, CEE, RSPCB

Delhi

15. Mr. S.M. Ali, Member Secretary, DPCC
16. Dr. Anil Kumar, Department of Environment, Delhi Government
17. Dr. M. P. George, DPCC
18. Mr. V. K. Saraswat, Transport Department Delhi

Discussions on the graded response action plan for NCR and directions given

EPCA said that the 'Graded Response Action Plan' to combat air pollution situations according to pollution levels in Delhi and NCR, which was prepared by CPCB in consultation with EPCA under directions of Supreme Court, has been adopted and notified by Gazette Notification dated 12th January 2017 of Central Government, and through this notification EPCA has been entrusted the task of implementing the 'Graded Response Action Plan' in Delhi and NCR and directing action.

EPCA said that considering the nature of actions to be taken under the 'Graded Response Action Plan' it is required that state level task force be constituted under Chief Secretary of concerned states in NCR for coordinating and overseeing the actions.

It was discussed that this function may be performed by the state level committee, which is headed by the Chief Secretary and has been formed by orders of NGT.

EPCA said that Central Government vide letter dated 13th January 2017 has further decided that the central level task headed by Chairman, CPCB will meet very frequently during periods of poor air quality. The CPCB headed task force is charged with informing EPCA of the different levels of AQI so that measures can be directed.

EPCA was informed that meetings at the CS level have been held in UP and Haryana and state level committee formed. It was discussed that LG Delhi also holds regular meetings on air pollution. CS, Delhi is also requested to take stock of actions in respect of the 'Graded Response Action Plan'. These regular meetings will help to increase compliance and enforcement of the measures under the action plan.

EPCA directed that based on the current air quality levels as monitored by CPCB, the graded plan would be in force in the 'Moderate to Poor' category in all districts of NCR. In Delhi, where the air pollution levels have been either 'Very Poor' or 'Severe', the Graded Action Response Plan would be Severe category in force. However, certain actions as detailed in the category of Very Poor or Severe would not be implemented till these were discussed further and implementation safeguards provided. These actions are noted below.

EPCA desired that special attention be paid to i) zero tolerance for garbage and leaf burning, ii) improving pavement, greening road sides, and keeping sides of the roads dust free, iii) taking action against brick kilns which have not converted to Zig-Zag type as directed by CPCB, iv) action against visibly polluting vehicles by deputing sufficient teams and mobile squads, v) strengthening PUC system through regular calibration, auditing and data integration, vi) expediting introduction of RFID for checking non-destined trucks.

EPCA directions to Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan for implementation of Graded Response Action Plan in the category of 'Moderate to Poor' are as follows :

1. All measures as detailed in the Moderate to Poor category of the Graded Response Action Plan are to be implemented immediately and stringently. The Chief Secretary headed state level committee should monitor all actions to ensure compliance.
2. All brick kilns, which have not installed improved emission technology, either zigzag or any other that have been vetted by the state pollution control board, will be closed. All efforts will be made to ensure that this measure in the Graded Response Action Plan can be fully implemented by next winter. State Pollution Control Boards must discuss the transition with existing brick kilns so that emission control and abatement measures are taken.
3. All thermal power plants in NCR will be strictly monitored by the State Pollution Control Board to ensure compliance with existing standards. CPCB will provide link to EPCA for remote monitoring of the online system for power plants in NCR.
4. State governments will take all steps to reduce dust pollution through mechanised sweeping and plantations on the side of the road. The dust pollution in Gurgaon was red-flagged for priority action. The Haryana government will address this issue and prepare a plan for its control.
5. State governments in NCR will urgently improve their pollution under control certification system. The Haryana government was directed to particularly review the current system of PUC, which has been found to be extremely inadequate and to prepare a time-bound plan for improvement. This is a priority action for the NCR states and will be audited by EPCA in the coming month.

6. Delhi government will undertake a special drive to target visibly polluting vehicles, which will be penalised heavily during this period. EPCA will be informed of the results of this drive.
7. All governments will take actions to enforce rules for dust control in construction activities.
The CS headed state level committee will ensure compliance and enforcement. State governments will inform builders of the provisions and the actions that are required for control of dust pollution in sites. All efforts will be made to disseminate this information publicly.
8. Haryana and Uttar Pradesh will provide turn-round facilities before entry into Delhi for commercial vehicles. This will allow governments to ensure that vehicles that are not destined for Delhi are turned back.
9. State governments will ensure that ash ponds are watered and pollution is minimised. Delhi government will ensure that the management of Badarpur Thermal Power Plant is required to take action, after February 1, 2017, to remove and dispose of the ash from the pond. The ash must be transported in vehicles that do not lead to air pollution.
10. All other measures must be monitored closely so that there is compliance.

EPCA directions to Delhi government for implementation of Graded Response Action Plan in the category of 'Very Poor and Severe' are as follows :

These are in addition to the steps that need to be enforced under the Moderate to Poor category.

1. Closure of brick kilns, hot mix plants and stone crushers.
2. Closure of Badarpur and steps to maximise use of natural gas based power plants.
3. Increase frequency of mechanised sweeping and sprinkling of water, particularly on road stretches with high dust generation.
4. Stop use of diesel generator sets. Delhi government is directed to list out the essential activities for which diesel generators will be allowed to operate so that compliance with this measure is made effective.
5. Stop use of coal/firewood in hotels and open eateries.

6. DPCC will undertake a time-bound study through a suitable agency to survey to identify all water or air polluting and hazardous industries in areas other than industrial areas and redeveloped industrial areas.

It was agreed that the implementation of the following measures included in the Very Poor and Severe categories would be kept on hold:

1. **Intensify public transport services and introduction of differential rates to encourage off-peak travel.** It was discussed that the current system is over-loaded and therefore the first step is to augment public transport systems in the capital. It was also discussed that studies would be done to look at the feasibility and implementation of the differential rates before this is implemented so that public transport is not further compromised.
2. **Enhance parking fee by 3-4 times.** It was agreed that the hike in parking fee must be implemented with simultaneous efforts to increase the enforcement against illegal parking. It was also discussed that the current penalties for illegal parking are stipulated under the Central Motor Vehicles Act and Rules (CMVR) are so low that they do not allow for any deterrence. It was agreed to discuss this further with the Ministry of Surface Transport and Highways and also the Delhi police so that enforcement could be improved.

EPCA directions to Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan to prepare for implementation of the measures listed under 'Very Poor and Severe' are as follows:

1. All state pollution control boards will enumerate the commercial and institutional generator sets that are installed in NCR. In addition, state governments will adopt a policy for ban of diesel generators, which are not for essential usage. This will then allow for implementation of the Graded Response Action Plan, which requires ban on generators for non-essential usage.
2. State governments will discuss the implementation of parking rates in NCR so that these can be hiked during periods of high pollution.
3. State governments will discuss plan for augmentation of public transport so that measures that require greater usage of this mode of transport during high pollution periods can be implemented.

Agenda: Increase of ambient air monitoring stations in NCR

The MoEF letter directing the Graded Response Action Plan (January 13, 2017) notes that the air quality index for implementation of Graded Response Action Plan should be based on the readings of at least 50 percent of the Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS). Currently there are 20 CAAQMS in Delhi (6 of CPCB, 6 of DPCC and 8 of SAFAR). In future the number shall become larger as more stations are set up in NCR and data from other stations are included. CPCB has also given a schedule for augmenting stations to the Hon'ble Supreme Court.

CPCB and SPCBs informed EPCA that the increase of air monitoring stations was under progress and they were confident that the schedule for implementation would be adhered to. The list of stations and schedule is annexed.

In addition, CPCB informed that an APP SAMIR has been developed where AQI for 33 cities can be seen. Data of all continuous monitoring station of CPCB, DPCC and IMD will be linked and this App will give a daily pollution forecast and health advisories.

MS, CPCB said that CPCB had given direction to state government officers in NCR in Nov-Dec 2016 covering various actions for air pollution abatement but when the progress was reviewed recently it was observed that many officers at ground level were not very much aware about the matter. Therefore, proper awareness among ground level officers in each state is very important.

It was agreed that the next meeting to review implementation of the above mentioned directives and measures would be held in two-weeks. In addition, EPCA would seek time with Chief Secretaries to discuss implementation of the Graded Response Action Plan and would request that the meetings be held in different regions of the NCR so that local officials are informed of the plan and accountability increased for enforcement.



Plan for strengthening of Air Quality Monitoring Stations

1.Haryana State Pollution Control Board

State	S.No.	Name of District HQ town	Existing Stations		Stations Planned	
			Manual	Real Time	Manual	Real Time
Haryana	1	Faridabad	2	1(CPCB)	NIL	2(CPSU+HSPCB)
	2	Gurugram	NIL	1(HSPCB)+1(IITM)	NIL	1(HSPCB)
	3	Mahendragagh	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	4	Bhiwani	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	5	Mewat	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	6	Rohtak	NIL	1(HSPCB)	2	NIL
	7	Sonepat	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	8	Rewari	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	9	Jhajjar	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	10	Panipat	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	11	Palwal	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	12	Jind	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
	13	Karnal	NIL	NIL	2	1(HSPCB)
Total			2	4	22	Total = 13 (1=CPCB+12=HSPCB)

2. Uttar Pradesh Pollution Control Board

State	S.No.	Name of District HQ town	Existing Stations		Stations Planned	
			Manual	Real Time	Manual	Real Time
UP	1	Meerut	2	NIL	NIL	3 (CPSU)
	2	Ghaziabad	2	NIL	NIL	1 (CPCB)
	3	Gautam Buddh Nagar	2	1 (ITM-Noida)	2 (Gr.Noida)	1 (CPCB in Noida) 1 (UPPCB in GN)
	4	Bulandsahar	2	NIL	NIL	1 (UPPCB Khurja)
	5	Baghpat	NIL	NIL	2	1 (UPPCB)
	6	Hapur	2	NIL	NIL	1 (UPPCB)
	7	Muzzafarnagar	NIL	NIL	2	1 (UPPCB)
Total			10	1	6	10

3. Rajasthan State Pollution Control Board

State	S.No.	Name of District HQ town	Existing Stations		Stations Planned	
			Manual	Real Time	Manual	Real Time
Rajasthan	1	Alwar	6 (3 in Alwar & 3 in Bhiwadi)	NIL	NIL	1-CPCB at Bhiwadi 1-RSPCB at Alwar
	2	Bharatpur	3	NIL	NIL	NIL
Total			9	0	0	2

4. Delhi Pollution Control Committee

State	S.No.	Name of District HQ town	Existing Stations		Stations Planned	
			Manual	Real Time	Manual	Real Time
Delhi	23	Delhi	10 (CPCB)	6 (CPCB) +4 DPCC +8(1MD)	NIL	20 (DPCC)
Total			10	18	0	20

यह मार्ग-निर्देशिका वेब-पोर्टल www.upecp.in पर भी उपलब्ध है।





**Reduce
Reuse
Recycle**

circle of life

पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०

विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ- 226 010

फोन : 0522-2300541, फैक्स : 0522-2300543

ई-मेल : doeuplko@yahoo.com